

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
26.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4251 का उत्तर

ट्रेन परिचालन में प्रणालीगत सुधार

4251. श्री जिया उर रहमान:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को पता है कि रेल परिचालन में प्रणालीगत सुधार की सख्त आवश्यकता है;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): भारतीय रेल में सुधार संबंधी कार्रवाई करना सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा और दक्षता बढ़ाने, यात्री अनुभव में सुधार लाने, नेटवर्क विस्तार में तेजी लाने आदि के लिए ये सुधार कार्य किए जाते हैं। हाल ही में, भारतीय रेल में निम्नलिखित सुधार कार्य किए गए हैं:-

(i) गति शक्ति निदेशालय/इकाइयाँ: प्रधान मंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) परिवहन क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं की योजना और निष्पादन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए 21 अक्टूबर को शुरू किया गया था।

भारतीय रेल ने अपनी परियोजना नियोजन प्रक्रिया में गति शक्ति के सिद्धांतों को तुरंत आत्मसात कर लिया है। मौजूदा संसाधनों का उपयोग करते हुए, भारतीय रेल में एक बहु-विभागीय गति शक्ति निदेशालय बनाया गया है। इसी तरह, क्षेत्रीय रेलों में गति शक्ति इकाइयाँ बनाई गई हैं। सभी हितधारकों और अन्य अवसंरचना मंत्रालयों/विभागों से परामर्श के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाती हैं।

उपर्युक्त पहलों के परिणामस्वरूप परियोजनाओं के मूल्यांकन/स्वीकृति प्रक्रिया और निष्पादन में तेजी आई है।

(ii) महाप्रबंधकों और मंडल रेल प्रबंधकों को परियोजनाओं की मंजूरी देने की शक्तियों में वृद्धि: परियोजनाओं के तेजी से निष्पादन के लिए महाप्रबंधकों और मंडल रेल प्रबंधकों के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए मंजूरी देने की शक्तियों में वृद्धि की गई है।

(iii) अनुबंधों को अंतिम रूप देना और उनका प्रबंधन करना: निविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए महाप्रबंधकों को संपूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। इसके अलावा, पारदर्शी और शीघ्र/त्वरित अनुबंध प्रबंधन और ठेकेदार की बिलिंग के लिए निर्माण कार्य अनुबंध प्रबंधन प्रणाली (आईआरडब्ल्यूसीएमएस) और ठेकेदार की ई-एमबी को लागू किया गया है।

(iv) कवच का विकास और कार्यान्वयन: रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा में सुधार लाने के लिए, कवच को भारतीय रेल में राष्ट्रीय स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली के रूप में

विकसित किया गया है। कवच के कार्यान्वयन का कार्य भारतीय रेल में मिशन मोड में किया गया है।

(v) समपारों का उन्मूलन: रेलगाड़ी परिचालन और सड़क उपयोगकर्ताओं की संरक्षा में सुधार के लिए, बड़ी लाइन पर बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा, ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण करके चरणबद्ध तरीके से सभी चौकीदार वाले समपारों को बदलने का भी निर्णय लिया गया है।

(vi) स्टेशन पुनर्विकास: भारतीय रेल ने यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने और रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ी परिचालन में दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए 1,337 स्टेशनों पर कार्य शुरू किया गया है।

(vii) आधुनिक रेलगाड़ियां चलाना: यात्री अनुभव को बढ़ाने और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए, भारतीय रेल में अत्याधुनिक वंदे भारत रेलगाड़ियां, आधुनिक सुविधाओं के साथ अमृत भारत रेलगाड़ियां और नमो भारत रैपिड रेल चलाई गई हैं।

(viii) भारत गौरव रेलगाड़ियां: भारतीय रेल ने भारत गौरव रेलगाड़ियों के नाम से थीम-आधारित पर्यटक सर्किट रेलगाड़ियां शुरू की हैं, जिसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र के पेशेवरों और अन्य सक्षम सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भारत और विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भव्य ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करना है।

(ix) स्टेशनों और रेलगाड़ियों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना: टिकटिंग सुविधा, खानपान इकाइयों आदि जैसे विभिन्न ग्राहक इंटरफेस बिंदुओं पर डिजिटल भुगतान सुविधा।

(x) माल परिवहन: माल ढुलाई बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रेल ने मालभाड़े में छूट, सुनिश्चित व्यवसायों पर छूट, लघु गमन दूरी पर रियायतें, मिनी रेक लदाव, माल शेडों का विकास, सामान्य प्रयोजन माल डिब्बा निवेश योजना (जीपीडब्ल्यूआईएस), व्यवसाय विकास पोर्टल आदि के रूप में कई उदारीकृत प्रोत्साहनों के रूप में बड़े सुधार किए हैं।

(xi) गति शक्ति कार्गो टर्मिनल: भारतीय रेल के माल लदान हिस्से को बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने और कार्गो टर्मिनलों की स्थापना में सुगमता के लिए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पहल शुरू की गई है। अब तक, 95 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कमीशन किए जा चुके हैं।

(xii) "संयुक्त पार्सल उत्पाद" विकसित करने के लिए रेलवे-भारतीय डाक का एकीकरण: व्यवसाय शुरू करने के लिए दो सरकारी विभागों के बीच एक संयुक्त सहयोगी पहल के रूप में, पार्सल सुपुर्दगी की एक संपूर्ण प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें डाक विभाग द्वारा आद्योपांत संपर्कता और रेलवे के माध्यम से स्टेशन से स्टेशन तक मध्यवर्ती संपर्कता प्रदान की गई है।

(xiii) कोयला श्रृंखला समन्वय समूह: कोयला श्रृंखला में बड़ी संख्या में हितधारक शामिल हैं जैसे कोयला कम्पनियाँ, निजी और वाणिज्यिक खदानें, बंदरगाह, बिजलीघर, उद्योग और भारतीय रेल। सभी हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए, रेल मंत्रालय में कोयला श्रृंखला समन्वय समूह स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

(xiv) वार्षिक भर्ती कैलेंडर: भारतीय रेल ने भर्तियों के लिए एक वार्षिक कैलेंडर जारी किया है, इससे न केवल अनिश्चितता और अभ्यर्थियों के लिए प्रतीक्षा अवधि कम होगी, बल्कि रेलवे में समय पर रिक्तियां भी भरी जा सकेंगी।

(xv) रेल भूमि नीति: प्रधान मंत्री गति शक्ति स्वरूप के तहत देश भर में तेजी से एकीकृत योजना और अवसंरचना के विकास को सक्षम बनाने के लिए रेल भूमि पट्टा नीति को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए, दीर्घकालिक भूमि पट्टा नीति जारी की गई है।

(xvi) रोलिंग ब्लॉकों की शुरुआत: राजपत्र अधिसूचना द्वारा 2023 में भारतीय रेल में रोलिंग ब्लॉकों की अवधारणा शुरू की गई है, जिसमें परिसंपत्तियों के एकीकरण/अनुरक्षण/मरम्मत/प्रतिस्थापन का कार्य रोलिंग आधार पर 52 सप्ताह पहले ही किए जाने की योजना बनाई गई है जिसे मंडलों द्वारा योजनानुसार निष्पादित किया जाएगा।
